भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *141
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।
9 श्रावण, 1948 (शक)

एआई डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा निवेश

***141. श्री कार्तिकेय शर्मा :**

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों और घरेलू समूहों द्वारा बढ़ते वैश्विक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) तटीय डेटा केंद्र के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता से एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति किस प्रकार सुदृढ़ होगी; और

(ग) क्या सरकार भारत में डेटा सेंटर के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति लाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ग)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

'एआई डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा निवेश' के संबंध में दिनांक 31.07.2026 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *141 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

*****

(क) से **(ग):** भारत का एआई मिशन प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन के तहत, सरकार एक संप्रभु एआई स्टैक का निर्माण कर रही है जिसमें गणना क्षमता, मूलभूत मॉडल और स्वदेशी अनुप्रयोग शामिल हैं।

डेटा सेंटर डिजिटल अवसंरचना पारिस्थितकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। भारत में डेटा सेंटर उद्योग स्थिर गति से बढ़ता आ रहा है। एआई और उच्च-कार्यनिष्पादन कंप्यूटिंग की तेजी से वृद्धि देश में डेटा सेंटर क्षमता की बढ़ती मांग को संचालित कर रही है।

डेटा सेंटर देश भर जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर में अवस्थित हैं। स्थापित क्षमता वर्ष **2020 में 375 मेगावाट** से बढ़कर वर्तमान में **लगभग 1575 मेगावाट** हो गई है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, कई वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों और घरेलू उद्योग जगत की बड़ी कंपनियों ने भारत में एआई अवसंरचना, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, एआई नवाचार और डिजिटल क्षमता निर्माण के लिए निवेश की घोषणा की। ये घोषणाएं भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते विश्वास और एआई बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में इसके उभरकर सामने आने की बेहतर स्थिति को दर्शाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय सब-सी केबल नेटवर्क और विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच के साथ तटीय डेटा हब सहित एआई-की दृष्टि से तैयार डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे का विकास, विश्व स्तर पर सम्बद्ध, लचीली और टिकाऊ डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इस तरह का बुनियादी ढांचा कम-विलंबता वाले अंतरराष्ट्रीय संपर्क का समर्थन करता है, बड़े पैमाने पर एआई कार्यभार को सक्षम बनाता है, क्लाउड और एआई सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेवा प्रदान करने वाले डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान देता है।

सरकार ने देश में डेटा सेंटर के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1) डेटा केंद्रों को बुनियादी ढांचे के उप क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण सूची (अक्टूबर, 2022) में शामिल किया गया है, जिससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहूलियत संभव हुई है।
2) डेटा सेंटर बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग मानदंडों को राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक (एनबीसीएस), 2026 में शामिल किया गया है।
3) केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत के डेटा केंद्रों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के संबंध में एक दीर्घकालिक घोषणा की है।
4) भारत सरकार हरित ऊर्जा मुक्त अभिगम नियमावली, हरित ऊर्जा गलियारा योजना, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, अपतटीय पवन वीजीएफ योजना और सौर पार्क योजना जैसे उपायों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।
5) विभिन्न राज्यों ने व्यापार आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर नीतियां प्रस्तुत की हैं। ये नीतियां मुख्य रूप से व्यापार सहुलियत (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस - ईओडीबी) और उद्योग के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित हैं।

****